LIVING CONDITIONS OF AGRICULTURAL LABOUR

*418. SHRI R. P. KHAITAN : †
SHRI JAGAT NARAIN :
SHRI KRISHAN KANT :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to safeguard the interests and to improve the living conditions of the agricultural labour, including fixation of minimum wages taking into account the increased income to the agriculturist due to the use of high yielding varieties of seeds and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) and (b) The subject matter of the question relates, in the main, to the State Sphere. The State Governments have been urged, from time to time, to fix/revise the rates of minimum wages of agricultural workers. In the case of employment in agriculture carried on by or under the authority of the Central Government, the statutory minimum wages were revised recently in May, 1969.

श्री आर०पी० खैतान : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो मिनिमम वेज है वह कौन कौन से प्रान्त में कितना कितना है और उनको क्या क्या और फैसिलिटीज़ दी जा रही है ? अगर आपके पास यह हो तो जरा बताने की कृपा करें ।

श्री भागवत झा आजाद : मिनिमम रेट्स आफ वेजेज़ हर एक स्टेट में अलग अलग हैं। उसकी लम्बी फेहरिस्त है । अगर मुझे कहा जाय तो मैं इसको टेबिल पर रख दूं और अगर पढ़ने को कहा जाय तो पढ़ूं ।

श्री सभापति : पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा तो टेबिल पर रख दीजिये ।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. P. Khaitan.

श्री भागवत झा आजाद : लम्बी लिस्ट है ।

श्री आर० पी० खैतान : कुछ मिनिमम वेज बता दें ।

श्री राजनारायण : कोई खास बात हो तो बता दें ।

श्री सभापति : जो खास बात बता सकते हों बता दें और बाकी टेबिल पर रख दें ।

श्री राजनारायण : पूरा न पढ़िये ।

श्री सभापति : कह तो दिया मैंने ।

श्री राजनारायण : उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार में क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : सेंट्रल गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार ने मई, 1969 में इसको रिवाइज़ किया था । मिनिमम 2 रुपय 50 पैसे है और अधिक से अधिक 3 रुपये 70 पैसे है । आंध्र में कम से कम 1 रुपया 50 पैसे और अधिक से अधिक 3 रुपये है । आसाम मे कम से कम 1 रुपया 50 पैसे और अधिक से अधिक 2 रुपये है । बिहार में 2 रुपये 50 पैसे, भागलपुर और मुंगेर जिले में है, 2 रुपये 50 पैसे संथाल परगाना जिले में है, यह कम से कम है, और 2 रुपये 50 पैसे कम से कम पूर्णिया जिले में है लेकिन अधिक से अधिक 2 किलो और 750 ग्राम धान और 500 ग्राम सत्तू है । यह अधिक से अधिक है । और गुजरात में . . .

श्री राजनारायण : क्या कहा 400 ग्राम सत्तू ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा 2 किलो और 750 ग्राम धान और 500 ग्राम सत्तू है ।

श्री जेड० ए० अहमद : सब कागज पर है, कुछ मिलता मिलाता नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : . . . और गुजरात में 1 रुपया 25 पैसा कम से कम और अधिक से अधिक 3 रुपया है । हरियाणा में 1 रुपया और

1 रुपया 25 पैसा कम से कम और अधिक से अधिक 2 रुपया और 2 रुपया 50 पैसे हैं। केरल में . . .

SHRI A. G. KULKARNI: These are paper figures or actual figures?

MR. CHAIRMAN: He is reading from a paper.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: These are the statements that have been provided by the State Governments which are the appropriate Government under the Act to fix the minimum wage.

श्री राजनारायण : यू० पी० में।

श्री आर० पी० खैतान : मेरा दूसरा सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आप लोगों ने प्रान्त वालों को मिनिमम वेजेज़ के लिये कुछ एडवाइस दी है और अगर दी है, तो क्या दी है ?

श्री भागवत झा आज़ाद : जैसा कि मैंने कहा, अध्यक्ष महोदय, कि नियम के अन्तर्गत एक्ट के अनुसार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है और यह उनके हाथ में है कि विभिन्न राज्यो में अलग अलग रखे। यह उनके ऊपर है कि कितना कम से कम और कितना अधिक से अधिक फिक्स करेंगी। मिनिमम वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत यह है। जनरल पालिसी जो विस्तार के साथ हो सकती है, वह योजना कमिशन और योजना में निहित है।

SHRI R. T. PARTHASARATHY: Is it not a fact that in the farm labour as well as plantation labour the basic minimum is only Re. 1.86 as per the law particularly in South India? Is it possible for any person with a family to eke out a living with only Re. 1.86; and there is a great demand from the local labour population that this should be raised to at least Rs. 2.50. What is it that the Government of India have done to advise the State Governments to raise it up to at least Rs. 2.50?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, the Act itself provides for periodical revision and we are from time to time, as the hon. Member himself has suggested, advising the State Governments to revise the minimum and it is they, the appropriate Government, who can do anything in the matter. We can only advise them to revise the wage from time to time.

SHRI JAGDISH CHANDRA DIKSHIT: Sir, a few years ago the Government of India had convened a national seminar on agricultural labour and some conclusions were arrived at there. May I know from the Government what follow-up action has been taken on the conclusions arrived at that seminar convened by the Ministry of Labour and which was presided over by the Minister?

Another question is, in 1957 the Ministry of Labour had organised a very comprehensive economic survey and also made a promise that periodical surveys would be undertaken. May I know what further measures were taken thereafter to examine the conditions of agricultural labour because such a survey is a great necessity before we take any action?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I am sorry I cannot say anything now about these two matters which the hon. Member has mentioned but I can say this that whenever such seminars or conferences are held on matters pertaining to State Governments we discuss the matters in them, all the State Governments represent their views and then the consensus or the decisions reached are passed on to the State Governments for their implementation. In regard to this specific seminar this must have been done.

SHRI D. THENGARI: The question is very comprehensive. I should like to know to what extent the assurance given to the Republican Party of India by the Government of India regarding distribution of land among the landless labour, particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes, has been fulfilled.

Secondly, may I know whether the Government of India has advised the State Governments on the criteria for fixation of minimum wage?

And thirdly what is the implementation machinery and how is it going to be made more effective than this advice from the Central Government to the States?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I am sorry; I hope the hon. Members will take offence that I am repeating the answer over and over again. The Minimum Wages Act itself provides that the appropriate Government is the State Government. From time to time the Central Government can only advise the State Governments to revise the minimum wages and that we are doing.

SHRI D. THENGARI: What I wanted to know was . . .

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I am coming. You have raised three points and I am taking up point by point. About implementation, as the Act stands at present, fixing of the minimum, implementation and seeing whether it is implemented or implemented in breach, all that is done by the State Governments. They have got the machinery and from time to time they see and check up the position.

SHRI LOKANATH MISRA: Bihar is under President's rule and what happens?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: President's rule has come only now. It does not mean that everything has been taken over by the Central Government.

SHRI JAGJIVAN RAM: Every time this question of President's rule is brought up, I want to make the position clear. It does not mean that you replace the machinery of the State Government and supplant it by the Central Government machinery. What it means is that those subjects which are State subjects can be raised in Parliament. It does not mean that our officers will go and supplant the State officers. I just wanted to remove this misconception.

श्री जेड० ए० अहमद : इस प्रश्न का ताल्लुक लगभग 40 फीसदी देश की आबादी से संबंध है। यह बड़ी चिंताजनक बात है कि जो वेजेज मुकर्रर हुए हैं, वह मार्केट रेट से कम हैं और उनको भी इन्फोर्स करने के लिये मिनिमम वेज की कोई मशीनरी नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या जवाब से आप खुद संतुष्ट हैं कि हमने सूबों को दे दी है इसकी जिम्मेदारी ? क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोई क़दम ऐसा नहीं उठा सकती, जिसमें कि सूबों को सही रास्ते पर लाया जाये, उचित वेजेज मुक़र्रर किये जायें और काफ़ी इफेक्टिव्ह मशीनरी उनको इन्फोर्स करने के लिये लागू की जाय। क्या इसमें आप कोई नया क़दम, उठाने के लिये तैयार हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय बात यह है कि जहां तक राज्य सरकारों के काम का ताल्लक है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे संविधान के अंतर्गत ठीक काम करें। संविधान के अंतर्गत हमारे एफेयर आफ वर्क अलग अलग हैं। तो सिवाय इसके कि हम उनसे निवेदन करें, आरजू करें, दख्वास्त करें और उनका ध्यान आकर्षित करें, हम किसी राज्य सरकार को डिसमिस तो नहीं कर सकते, मजबूर तो नही कर सकते। कैसे कर सकते हैं, जब तक कानून की व्यवस्था न हो। इसलिये इस मामले में इतना ही कर सकते हैं कि जहां कहीं महसूस करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निष्क्रांत सम्पत्ति

*412. **श्री ना० कृ० शेजवलकर ।**
श्री सुन्दर सिंह भंडारी :
श्री पीतांबर दास :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न विभागों में निष्क्रान्त सम्पत्ति के कितने मामले विचाराधीन है;

(ख) गत दो वर्षों में किस-किस प्रकार के कितने-कितने मामले नये सिरे से उठाये गये ;